'बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 311]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 16, शक 1932

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 (अग्रहायण.16, 1932)

क्रमांक-12502/विधान/2010 .—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ . विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2010 (क्रमांक 29 सन् 2010) पुर:स्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> हस्ता./ (**देवेन्द्र वर्मा)** सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक (क्रमांक 29 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2010

वित्तीय वर्ष 2010-2011 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2010 कहलायेगा.

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए राज्य की संचित निधि में से 10,33,72,59,800 रुपयों का दिया जाना. 1.

2.

छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनिधक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2010 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए एक हजार तैतीस करोड़ बहत्तर लाख, उन्सठ हजार, आठ सौ रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग.

इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां,

ं अनुसूची (घारा 2 और 3 देखिये)

277777	सेवाएं और प्रयोजन	और प्रयोजन निम्नलिखित से अन्ति		नेम्नलिखित से अनधि क	धेक राशिया	
अनुदान का . संख्यांक	स्वार्जारप्रवाजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग	
(1)	(2)	••	4	(3)	•	
			रुपये	रुपये	रुपये	
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	5,79,52,000	27,94,000	6,07,46,000	
03	पुलिस	राजस्व	6,00,00,300	0 .	6,00,00,300	
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	1,30,00,000	0	1,30,00,000	
05	जेल	राजस्त	11,30,100	0	11,30,100	
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	9,70,00,000	0	9,70,00,000	
·10	वन	राजस्व	1,16,55,000	0	1,16,55,000	
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	10,00,00,000	0	10,00,00,000	
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	20,62,70,000	0	20,62,70,000	
13	कृषि	राजस्व	30,67,09,000	0.	30,67,09,000	
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,00,00,000	0	1,00,00,000	
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय	राजस्व	2,55,00,000	0	2,55,00,000	
, L D .	पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	पूंजी	12,00,00,000	0	12,00,00,000	
16	मछली पालन	राजस्व	18,23,000	0 -	18,23,000	
17	सहकारिता	पूंजी	2,85,000	0	2,85,000	
18	श्रम	राजस्व	58,60,000	0	58,60,000	
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	32,66,80,000	0	32,66,80,000	
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	31,93,00,000	0	31,93,00,000	
40	Part and A state, at a detail and	•	• • •			

(1)	. (2)	•		(3)	,
			रुपये	रुपये	रुपयें
	जल संसाधन विभाग	पूंजी	20,00,00,000	0	20,00,00,000
23	लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल	पूंजी	700	0 .	700
24	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	26,00,000	. 0	26,00,000
26	स्कूल शिक्षा	राजस्व	8,45,00,100	0	8,45,00,100
27	स्कूल सिद्धा	पूंजी	100	0	100
• 0	राज्य विधान मंडल	राजस्व राजस्व	78,80,000 .	0	78,80,000
28	राज्य वियान मङ्क न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	30,27,75,000	85,00,000	31,12,75,000
·29	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित	राजस्व	1,00,00,000	0	1,00,00,000
30		पूंजी	12,00,000	0	12,00,000
31	व्यय. योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से	रूपा राजस्व	100	0	100
	संबंधित व्यय.			0	9,07,65,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	9,07,65,000	. 0	100
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	100	0	
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
4.1	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	1,29,69,55,100	0	1,29,69,55,100
41	अनुसूचित अनेजाति उपयोजना	पूंजी	53,91,40,000	0	53,91,40,000
42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित	पूंजी पूंजी	100	0	100
	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.		15 00 000	. 0	15,00,000
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	15,00,000	0	20,00,300
44	उच्च शिक्षा	राजस्व • —	20,00,300	0	500
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी ———	500	0	6,40,00,400
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग	राजस्व	6,40,00,400	0	200
	`	पूंजी	200	0	22,40,000
49	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	22,40,000	.0	1,50,00,000
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	1,50,00,000	. 0	5,77,27,100
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	5,77,27,100		3,72,85,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	3,72,85,000	0	100
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	100	. 0	
59	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित	राजस्व	2,28,00,000	0	2,28,00,000
	विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	राजस्व	7,47,51,000	0	7,47,51,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	पूंजी	10,00,000	. 0	10,00,000
	0 0		100	. 0	100
65	विभाग	राजस्व	10,32,20,000	. 0	10,32,20,000
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	1,00,00,000	0	1,00,00,000
67	लोक निर्माण कार्य - भवन	राजस्व	30,00,300	. 0	30,00,300
		पूंजी		0	80,70,000
. 79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	80,70,000	0	3,00,00,100
		पूंजी	3,00,00,100	0	1,65,73,15,000
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय	राजस्व	1,65,73,15,000	.0	50,00,00,000
٠ .	सहायता.	पूंजी .	50,00,00,000		2,15,70,75,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	2,06,93,75,000	8,77,00,000	٠٠٠ و ١٦٠ و

(1)	(2).	•		(3)	
			रुपये	रुपये	• रुपये
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	पूंजी	38,00,00,000	0	38,00,00,000
	योग	राजस्व	8,46,36,38,800	9,89,94,000	8,56,26,32,800
		पूंजी	1,77,46,27,000	0	1,77,46,27,000
	वृहद योग		10,23,82,65,800	9,89,94,000	10,33,72,59,800

उद्देश्यों और कारणों का कथन

- यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर: स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदारों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.
- 2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

दिनांक 4 दिसम्बर, 2010

डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री, (भारसाधक सदस्य)

" संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित "

देवेन्द्र वर्मा सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा.